सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुःख होता है।

-चाणक्य

हैलो सरकार

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉग ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें
फोन: 0141-2202717
मो: 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

वर्ष-23 | अंक-256 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, बुधवार 21 मई , 2025 | पृष्ठ-4 | मूल्य: 2.50

राजस्थान के 4 जिलों में बम ब्लास्ट की धमकी

जयपुर। राजस्थान के टोंक, राजसमंद, पाली और भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। टोंक में भाजपा की तिरंगा यात्रा से पहले कलेक्टर की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर धमकी भेजी गई, जिसमें दोपहर 3=30 बजे ब्लास्ट की बात कही गई।

इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाकर बम निरोधक दस्ते ने सर्च अभियान शुरू किया। भारी पुलिस बल तैनात है और किसी को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। राजसमंद, पाली और भीलवाड़ा में भी इसी तरह के ईमेल मिले, जिसके बाद वहां भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

साइबर विशेषज्ञ जांच में जुटे

बता दें, साइबर विशेषज्ञ ईमेल भेजने वाले का पता लगाने में जुटे हैं, लेकिन वीपीएन के उपयोग के कारण जांच में चुनौतियां आ रही हैं। राजसमंद कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने बताया कि धमकी भरे ईमेल के बाद परिसर को खाली करवाकर जांच शुरू की गई। एसपी मनीष त्रिपाठी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताते हुए कहा कि आईपी एड्रेस ट्रैक कर आरोपी के

खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

इससे पहले 15 मई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और आईएएस नीरज के पवन को जान से मारने और जयपुर के स्वस स्टेडियम को उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद हाई अलर्ट जारी किया गया था।

गोविंद सिंह डोटासरा ने पूछा सवाल

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर..राजस्थान में हो क्या रहा है? मुख्यमंत्री जी को तीन बार जान से मारने की धमकी के बाद आज प्रदेश में कई जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ऐसे समय में मिली है जब 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान आने वाले हैं, ऐसे में प्रदेश के कई जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी अत्यंत गंभीर और राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है।

उन्होंने कहा कि सीकर जिला कलेक्ट्रेट में मुख्य सचिव अधिकारियों की बैठक लेने वाले थे, उस से पहले कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी बताती है कि राजस्थान में क़ानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। ये पहला मौका नहीं है, आए दिन मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारियों तक को धमकियां मिल रही हैं। अगर राज्य के मुखिया और विभाग ही सुरक्षित नहीं है तो आमजन की सुरक्षा का क्या हाल होगा?

डोटासरा बोले कि पिछले महीने 3 अप्रैल को भी जयपुर जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को जेल से कई बार धमकियां मिल चुकी है। लेकिन बावजूद इसके सरकार सोई हुई है और मुख्यमंत्री जी तमाशा देख रहे हैं।

टीकाराम जूली ने साधा निशाना

नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान के टोंक, राजसमंद, पाली और भीलवाड़ा जिलों में कलेक्ट्रेट भवनों को बम ब्लास्ट से उड़ाने की धमकी मिलना अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विषय है। दो दिन बाद देश के प्रधानमंत्री राजस्थान आने वाले हैं, और उससे ठीक पहले चार जिलों में कलेक्ट्रेट भवनों को बम ब्लास्ट से उड़ाने की धमकी मिलना, प्रदेश की कानून-व्यवस्था की असलियत को उजागर करता है। आएं दिन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अधिकारीयों को धमकियां मिल रही है और सरकार मौन होकर ये सब देख रही है द्य जूली ने कहा कि आज सवाल सिर्फ सुरक्षा का ही नहीं, बल्कि सरकार की विफलता, सुस्त खुफिया तंत्र और जनता की सुरक्षा के भरोसे पर उठती आशंकाओं का है। मुख्यमंत्री जी आपका गृह विभाग कौन चला रहा है?

देशी घी तस्करी का बड़ा खुलासा-अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 2 करोड़ की घी बरामद

दौसा, महवा। महवा थाना पुलिस ने घी तस्करी के अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 करोड़ रुपये से अधिक के देशी घी की धोखाधड़ी का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट एजेंसी मालिक और उसके साथी शामिल हैं। पुलिस ने एक 12 चक्का टैंकर भी जब्त किया है जिसमें घी की तस्करी की जा रही थी।

कैसे हुआ घोटाला

दाऊजी मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड, महवा से महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित सनफ्रेश एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को 21,850 किलो देशी घी भेजा गया था। ट्रांसपोर्ट का जिम्मा उज्जैन की योगेन्द्र देव पांडे ट्रैवलिंग एजेंसी को सौंपा गया। 11 मई की रात 9=15 बजे टैंकर रवाना हुआ, जिसे संजय नामक ड्राइवर चला रहा था।

कुछ दिनों बाद कंपनी ने जब संपर्क किया तो ड्राइवर ने घी से लदा टैंकर दुर्घटनाग्रस्त होने की झूठी कहानी सुनाई और बताया कि सारा घी बह गया है। न तो किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, न ही किसी दुर्घटना की जानकारी दी गई।

पुलिस की पैनी जांच

महवा थाना प्रभारी राजेन्द्र मीना

के निर्देशन में बनी विशेष टीम ने राजस्थान और मध्यप्रदेश के करीब 800 किलोमीटर क्षेत्र में फैले संदिग्ध रूटों की जांच की। भरतपुर, धौलपुर, मुरैना, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर सहित कई जिलों में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। साइबर सेल की मदद से 100 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की ष्टष्ठक्र रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया।

आखिरकार साइबर और तकनीकी सर्विलांस से संदिग्धों की मूवमेंट की पुष्टि हुई और पुलिस टीम ने घेराबंदी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तस्करों की निशानदेही पर धौलपुर की ओम शंकर मिल्क फैक्ट्री से 18 टन (18,000 किलो) देशी घी जब्त किया गया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये आंकी गई है।

पकड़े गए तस्कर

संजय मालवीय पुत्र घीसा मालवीय उर्फ सुभाष, निवासी खजूरी थाना कानड़ा जिला आगर, हाल निर्माण नगर, इटावा। योगेन्द्र देव पांडे पुत्र ओमशरण पांडे, निवासी छाया नगर, उज्जैन। रोहित प्रजापत पुत्र कैलाश, निवासी कलसाडा खुर्द, थाना शादलपुर, जिला धार। पवन बघेल पुत्र रामप्रकाश, निवासी बामोर कलां, थाना बामोर, जिला मुरैना।

बड़ी कामयाबी, गहराई से साजिश

पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि आरोपी वर्षों से घी तस्करी के धंधे में लिप्त थे और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का दुरुपयोग कर माल को रास्ते में ही बेच देते थे। महाराष्ट्र पहुंचने से पहले ही देशी घी को धौलपुर के ओम शंकर मिल्क फैक्ट्री में बेचने की तैयारी थी। यह गिरोह पूरे प्रदेश में फैला था और कई बार ड्राइवर और एजेंसियों की मिलीभगत से कंपनियों को चूना लगाते थे।

पुलिस टीम को बधाई

थानाधिकारी राजेन्द्र मीना के नेतृत्व में एएसआई सुरेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल रवीन्द्र कुमार, भागीरथ, राजेश कुमार, महेश, सोनवीर व लख्मी की टीम ने सूझबूझ से न सिर्फ तस्करी को रोका बल्कि बड़े स्तर पर माल की बरामदगी भी करवाई।

कोई पाकिस्तान या नेपाल की नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की देते हैं मिसालें-सचिन पायलट

जयपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को भारतीय लोकतंत्र की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दुनिया में कई देश हैं, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है, लेकिन भारत का लोकतंत्र सबसे जीवंत और दृढ़ है।

उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज कई बड़े देश हमारे लोकतंत्र का उदाहरण देते हैं। कोई भी पाकिस्तान के लोकतंत्र की मिसाल नहीं देता है। कोई श्रीलंका या नेपाल का उदाहरण नहीं देता। सभी भारतीय लोकतंत्र की बात करते हैं। मुझे लगता है कि यह मुकाम सभी प्रधानमंत्रियों के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप ही प्राप्त हो पाया है, तो ऐसी स्थिति में इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस का योगदान इस दिशा में सबसे ज्यादा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने ही इस देश में सबसे लंबे समय तक शासन किया है, ऐसे में निश्चित तौर पर कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र को नया आकार दिया है।

उन्होंने राजीव गांधी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वह बहुत ही कम समय तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन बहुत ही अल्पकाल में उन्होंने कई अभूतपूर्व कदम उठाए। उन्होंने युवाओं को मतदान का अधिकार दिया। संचार क्रांति उन्हीं की देन है। उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए, जिसके परिणामस्वरूप आज विकास की गति तेज हुई है।

इसके अलावा, सचिन पायलट ने आतंकवाद को लेकर भी अपने सख्त रुख का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी आतंकवाद को लेकर अपनी बात कह चुका हूं। आतंकवाद को लेकर किसी भी प्रकार का किंतु-परंतु नहीं होना चाहिए। आतंकवाद से हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में हम सभी लोगों को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को परास्त करने के लिए एकजुट होना होगा।

साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर

की भी तारीफ की। उन्होंने जिस तरह से हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसे लेकर मैं अपनी सेना को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने जिस बहादुरी से पाकिस्तानी आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। इसके अलावा, न केवल सैनिकों बल्कि उनके परिवारों को भी धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने अपने वीर सपूतों को सीमा पर देश की रक्षा के लिए भेजा। भारतीय सेना देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहती है।

उन्होंने युद्धविराम को लेकर कहा कि जिस तरह से किसी तीसरे मुल्क ने युद्धविराम की घोषणा की, वह अप्रत्याशित था। युद्धविराम की घोषणा के बाद पाकिस्तान ने हमले किए। उसने सीमा पर गोलीबारी की और मोर्टार दागे। इसमें कई निहत्थे लोगों की जान गई।

कांग्रेस नेता ने आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को आर्थिक सहायता दिए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से आर्थिक सहायता दी गई, उससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। यही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति यहां तक कह देते हैं कि हम आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ व्यापार करेंगे। अब ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान अपने संसाधनों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए नहीं करेगा। वह आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए सरकार को इस मुद्दे को लेकर अपनी बात स्पष्ट कर देनी चाहिए।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर को लेकर कहा कि यह एक द्विपक्षीय मुद्दा है। इस विषय का किसी भी कीमत पर अंतरराष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए।

राजस्थली के सेन्ट्रलाईज इन्वेन्ट्री, सेल्स, बिलिंग एवं एयर कार्गो कॉम्पलेक्स के सॉफ्टवेयर ''सरल'' की लॉचिंग

जयपुर,। प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसिको) के सेन्ट्रलाईज इन्वेन्ट्री, सेल्स, बिलिंग एवं एयर कार्गो सॉफ्टवेयर 'सरल' की मंगलवार को सचिवालय में लॉचिंग की।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि राजसिको द्वारा संचालित एयर कार्गो कॉम्पलेक्स ईआरपी वर्तमान में लगभग 9000 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट- इम्पोर्ट करता है। इनबाउंड

कार्गो रजिस्ट्रेशन, वालेट आधारित डिजिटल प्रिडिपोजिट अकाउन्ट पीडीए द्वारा पेमेंट गेटवे ऑपरेशन, उत्पाद कार्यों का मास्टर एयरवे बिल नम्बर द्वारा पृथक्कीकरण, एक्सपोर्टर इम्पोर्टर का रजिस्ट्रेशन, वेयर हाउस मैनेजमेंट, टर्मिनल स्टोरेज एण्ड प्रोसेसिंग चार्जेज आदि कार्यों को सरल सॉफ्टवेयर द्वारा सम्पादित करने पर समय की बचत एवं शीघ्र निष्पादन होगा।

सरल सॉफ्टवेयर द्वारा राजस्थली में उत्पाद, उत्पाद बार कोडिंग, डिजिटल बिल, राजस्व , जी. एस.टी. आदि सभी कार्य केन्द्रीकृत रूप से किए जाएंगे जिससे पारदर्शिता, बेहतर सुपरविजन के साथ-साथ समय की बचत होगी। इस प्रकार न केवल डेटा जनरेशन होगा अपितु उत्पादों की बर्बादी रोकी जा सकेगी, उत्पादों की समयबद्ध सप्लाई तथा विपणन किया जा सकेगा। परचेज मैनेजमेंट, जी.एस.टी. मैनेजमेंट तथा उपभोक्ता संतुष्टिकरण में भी यह सॉफ्टवेयर सहायक होगा।

इस अवसर पर राजसिको की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. आरूषि अजेय मलिक ने बताया कि राजस्थानी हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री के लिए लंदन, सिंगापुर, दुबई, आगरा, जयपुर, आमेर, पुष्कर, सुमेरपुर (बांध के समीप), सवाई माधोपुर शहर, माउण्ट आबू जैसलमेर, हरिद्वार, बद्रीनाथ आदि देश-विदेश के प्रसिद्ध शहरों एवं प्रमुख एयरपोर्टस, तीन/पाँच सितारा होटलों के परिसरों में फ्रैंचाईजी मोड पर 'राजस्थली' विक्रय केन्द्र संचालित करने का भी निर्णय लिया गया है।

जमीन नापने गई टीम पर हमला

गाड़ी समेत बनाया बंधक, सांगानेर सदर थाने में हमलावर श्रवण चौधरी व साथियों पर केस दर्ज

जयपुर। सांगानेर तहसील के शियों सिंह पूरा कलावाला गांव में सीमांकन के दौरान शांति से कार्य कर रही टीम पर करीब 10 से 15 लोगों के समूह ने हमला कर उन्हें बंधक बना लिया, गाली-गलौज की और उनकी बोलेरो गाड़ी पर अवैध कब्जा कर लिया। पीड़ितों ने आरोपी श्रवण चौधरी व उसके साथियों के खिलाफ सांगानेर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना दिनांक 16 मई को उस समय घटी जब सर्वे टीम की टीम अपने स्वामित्व वाली भूमि पर पहुंची ,जिसकी सीमांकन की प्रक्रिया पहले ही 4 मई को हल्का पटवारी की मौजूदगी में पूरी की जा चुकी थी, और उसमें क्षेत्रीय काश्तकारों हिम्मत सिंह यादव एवं श्रवण चौधरी के प्रतिनिधियों की सहमति भी दर्ज की गई थी।

16 मई की सुबह 10 बजे से सीमांकन का कार्य शुरू हुआ, जो कि शाम करीब 6-7 बजे तक चला। कार्य लगभग पूरा ही होने वाला था कि उसी दौरान आरोप है कि श्रवण चौधरी, हिम्मत यादव और उनके साथ करीब 10-15 लोग दो गाड़ियों में सवार होकर मौके पर पहुंचे। इन लोगों ने कथित रूप से खेत में लगी तारबंदी को लांघा और सीधे जमीन में घुसकर हमला बोल दिया।

हमले के दौरान पीड़ितों को चारों ओर से घेरकर बंधक बना लिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। बताया गया कि टीम के सदस्यों को पीटा गया और इनके सिर, चेस्ट और कंधे पर गंभीर चोटें आईं। बोलेरो गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया और हथियार होने की धमकी देकर डराया गया।

घटना की जानकारी मौके पर बंधक बने लोगों ने तुरंत सांगानेर सदर थाने को सूचित किया। पुलिस लगभग रात 8=30 बजे मौके पर पहुंची और सभी पीड़ितों को छुड़ाया।

आवेदन के अनुसार, हमलावरों ने मिलकर संगठित तरीके से आपराधिक अतिचार किया, सीमांकन प्रक्रिया को बाधित किया और सरकारी आदेशों को चुनौती दी। पीड़ितों ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम का कुछ वीडियो फुटेज भी उनके पास है, जिससे हमलावरों की पहचान संभव है। पुलिस ने पीडितों शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 329(3), 115(2), 126(2), तथा 3(5) क्चहस् के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच स्ढ्ढ रामावतार कर रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि आरोपियों की पहचान कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम ग्रेटर की सख्ती-अस्थायी अतिक्रमण पर 25 हजार कैरिंग चार्ज वसूला, 3 केन्टर सामान जब्त

जयपुर। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रूकमणि रियाड़ के निर्देषानुसार उपायुक्त सतर्कता अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को सतर्कता शाखा की टीम द्वारा नगर निगम जयपुर ग्रेटर

के क्षेत्राधिकार में एसएफएस चौराहे से मानसरोवर प्लाज़ा तक व वैशाली नगर, आम्रपाली सर्किल के पास, राठौड़ नगर, मालवीय नगर ए ब्लॉक झालाना ग्राम, गंगा मार्ग सीबीआई फाटक, खो-नागोरियान फ्रेण्डस कॉलोनी, आगरा रोड़ से बन्धे तक, गेटोर रोड़ जगतपुरा से अस्थाई अतिक्रमण को करने वालों के विरूद्ध 25 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल कर 3 केन्टर सामान जब्त किया गया।

उपायुक्त सतर्कताअजय कुमार ने बताया कि नगर निगम ग्रेटर क्षेत्राधिकार में एसएफएस चौराहे से मानसरोवर प्लाज़ा तक व वैशाली नगर, आम्रपाली सर्किल के पास, राठौड़ नगर, मालवीय नगर ए ब्लॉक झालाना ग्राम, गंगा मार्ग सीबीआई फाटक, खो-नागोरियान फ्रेण्डस कॉलोनी, आगरा रोड़ से बन्धे तक, गेटोर रोड़ जगतपुरा से अस्थाई अतिक्रमण हटवाया गया। उपरोक्त कार्यवाही के दौरान 3 केन्टर सामान जब्त कर गोदाम में भिजवाया गया व अस्थाई अतिक्रमण करने वालों से मौके पर 25 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल किया गया तथा दौरे के दौरान कार्यवाही सतर्कता टीम द्वारा मौके पर समझाइष करते हुए मौखिक पाबंद करवाया कि भविष्य में अस्थाई अतिक्रमण समय से हटा ले अन्यथा नगर निगम जयपुर ग्रेटर के क्षेत्राधिकार में अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध भारी चालान या प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

दौसा में तिरंगे के सम्मान में निकलेगी गर्व यात्रा, ऑपरेशन सिन्दूर के शौर्य को सलाम

दौसा। देश की आन-बान और शान का प्रतीक तिरंगा जब सड़कों पर लहराता है, तो सिर्फ कपड़ा नहीं, भारत मां का गौरव चल पड़ता है... कुछ ऐसा ही नज़ारा 21 मई को दौसा की सरज़मीं पर देखने को मिलेगा, जब ऑपरेशन सिन्दूर में भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अद्वितीय प्रदर्शन को सम्मान देने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी।

यह गर्व यात्रा 21 मई को शाम 4=30 बजे सहज नाथ महादेव मंदिर (संस्कृत कॉलेज) से शुरू होकर गांधी तिराहे तक जाएगी। यह यात्रा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि उन रणबांकुरों के लिए श्रद्धा का सैलाब होगी जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए सीना तान दिया।

भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. प्रभु दयाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आयोजन ऑपरेशन सिन्दूर के माध्यम से देश को गौरवान्वित करने वाली भारतीय सेना को जनभावनाओं से जोड़ने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में कई दिग्गज नेता व जनप्रतिनिधि भाग लेंगे।

तिरंगे की शान में उमड़ेगा जनसैलाब

इस यात्रा में शामिल होंगे = प्रभारी मंत्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़, भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर, प्रदेश मंत्री एवं तिरंगा यात्रा संयोजक भूपेंद्र सैनी, संभाग संयोजक प्रेम सिंह बनवास, जिला संगठन प्रभारी संजय सिंह नरूका, बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा, लालसोट विधायक रामविलास मीणा, सिकराय विधायक विक्रम बंसीवाल, महवा विधायक राजेंद्र मीणा।

यात्रा में दौसा जिले के व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संगठनों, समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों व सर्व समाज के पदाधिकारियों की भागीदारी भी रहेगी, जो तिरंगे के सम्मान में एक स्वर में राष्ट्रभक्ति का जयघोष करेंगे।

देशभक्ति का होगा जीवंत प्रदर्शन

जिला मीडिया प्रभारी व संयोजक दीपक जोशी ने बताया कि तिरंगा यात्रा में विशेष आकर्षण रहेंगे = 501 मीटर लंबा विशाल तिरंगा झंडा, राष्ट्रभक्ति से सराबोर

झांकियां, गूंजते डीजे व ढोल की थाप, रास्ते भर पुष्प वर्षा, भारत माता के जयकारों से गूंजते नारे।

यात्रा के समापन पर गांधी तिराहे पर भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। यह क्षण न केवल भावनाओं को उद्वेलित करेगा, बल्कि हर दौसावासी के हृदय में देशभक्ति की लौ और प्रज्वलित कर देगा।

मनुष्य का संस्कार अच्छा होना जरुरी है

यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका कर्तव्य है कि उसे सफलता पूर्वक करें जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा छुट्टी के दिनों में ईश्वर का ध्यान करें क्योंकि यही सबसे सही वक़्त होता है उसे जानने की इसमें किसी को बुरा लगता है तो लगने दीजिये ईश्वर आपको ऐसा बना देगा कि किसी भी संकट में आपको मदद करेगा लोग क्या बोलते हैं इसपर जाने की जरुरत नहीं है जहाँ तक सेहत का सवाल है ईश्वर ही साथ देने वाला है और डरने की बिलकुल जरुरत नहीं है क्योंकि ईश्वर की आराधना से आपको क़ोई छू भी नहीं सकेगा और घर की छोड़िये बाहर लोग आपको अच्छा मानते हैं तो आप सही हैं

(लेखक-संजय गोस्वामी)

नर और नारी एक समान है आप नारी हो या नर, संस्कार अच्छा होना बहुत जरुरी है संस्कार ठीक नहीं है तो क़ोई भी मनुष्य सही या गलत की पहचान नहीं कर सकता है नारी में माँ का रूप से बड़ा और क़ोई नहीं है क्योंकि जन्म देती है आप दूसरे को उपदेश देने से पहले खुद ही अंदर झाँक कर देखिए आप के अंदर ईश्वर मौजूद है ना तो डरता है ना ही डराता है एक बात समझ कर चलिए आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाये तब आप समझ जायेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा दूसरों की देखा देखी करना ठीक नहीं है आप खुद ही ऐसा सोचे यदि हम उस जगह रहते तो क्या करते कहाँ जा रहा है आज का समाज इसपर ध्यान देने की जरुरत है दूसरे को दु:ख को उसके बुरे वक़्त में नजरअंदाज करना आपकी सबसे बड़ी भूल है हम जब अकेले थे तो माता पिता मेरे साथ थे खुश थे कहीं शिफ्ट करना भी आसान था ईश्वर सब देख रहा है आप भगवान राम से प्रेरणा लें उस समय पिता के वचन को निभाना सबसे बड़ा कर्तव्य था उन्हें यानि राजा दसरथ को श्रवण कुमार की गलती से मारे जाने पर उनके माता पिता से श्राप के कारण यह देखने को मिला जिसे उन्हें भी काफी दु:ख हुआ लेकिन नियति को कौन टाल सकता है और ऐ हुआ जंगल जाना वो भी 14वर्ष के लिए इतना आसान नहीं था वो वनवास श्री राम को ही मिला था लेकिन उनके साथ माता सीता और भ्राता लखन भी गए ऐ निर्णय भी आसान नहीं होता है आप कल्पना कर देखिए आप घबराहट में बैचैन हो जायेंगे क्योंकि 14वर्ष जंगल में रहना क़ोई आसान काम नहीं होता है ऐ मरने जीने जैसा है लेकिन यदि आप सही में जिसे सच्चे मन से चाहते हैं उसे मौत से भी डर नहीं होता और वहाँ ना तो घर है ना ही पलंग ना ही बिजली पानी और खाने हेतु गैस का सिलेंडर लेकिन हिम्मत है और यही हिम्मत उसे महान बनाता है जो दु:ख में साथ है वही आपका सच्चा आदमी है चाहे अपना हो या पराया, माता सीता ऐसा नारी बनना इतना आसान नहीं है लेकिन जीवन में भगवान श्री राम के साथ मरने जीने की इच्छा ही पुरे विश्व में माँ के रूप में पूजन किया जाना गर्व की बात है मैं आपको कहुँ कि माँ के रास्ते पर चलना चाहिए तो बुरा भी लगेगा लेकिन जीवन में दु:ख के समय खुश रहना भी आएगा आप खुद को विचारों में अच्छा बनने की कोशिश करें विचार ही आपको महान बना सकती है इसमें कई कष्ट भी होंगे लेकिन जो सही लगता है उसे करें आपका धर्म क्या है ऐ देखिए यदि आप अपने धर्म को सही से निभाना आ गया तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपके रास्ते चल पड़ेगी और कुछ बन कर निकलेगी और जहाँ जायेंगे आपका मान सम्मान बढ़ेगा आप यदि किसी पर गुस्सा हैं हैं तो पहले एक पल के लिए शांति से काम लें और उस आदमी को पहले परख लीजिये उसमें कितना ईश्वर ने शक्ति दि है ज्ञान से और उसके कर्म से मालूम हो जायेगा कष्ट जीवन में आते हैं एक गाना है जो संतोष आनंद द्वारा लिखा है एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है... इसमें दु:ख और सु:ख दोनों पर सब खुश रहते हैं गुरुगोबिंद सिंह जब खालसा पंथ की स्थापना कर रहें थे तब उन्होंने पूछा की कौन मुझे शीश दे सकता है आम सभा में सभी हैरान हो गए तब एक उनका भक्त ने आवाज़ लगाया मैं दूंगा और तब तम्बू में बाहर खून को देखकर लोग हैरान थे कि लगता है शीश कट गया है लेकिन बाद में दूसरा डरा नहीं और ऐसे कर पांच आदमी चले गए और बाद में सब सही सलामत निकलें यही गुरुजी जाँचना चाहते थे कि मौत से डर है या मुझसे और पंच प्यारे कहलाये, जो गुरू के अमृत का पान किया यहाँ अमृत है मौत को मात देकर गुरु का सच्चा भक्त अत: आज समाज में संस्कार को महत्व देने की जरुरत है यदि आपके पास अच्छा संस्कार नहीं मिला तो पाने की कोशिश करें आज आधुनिकता की दौड़ में बहुत से मनुष्य इतना अंधा हो गए है कि शादी के बाद ना तो अपने माँ को पूछता है ना तो पिता को सम्मान देता है बुरे वक़्त में तो उन्होंने अपने को कष्ट में रखकर अबको इस काबिल बनाया कि आप आज खा कमा कर परिवार में अपना धर्म निभा रहें हैं ऐ कैसा समाज, क़ोई खुद ही क्लबो में जाता है और जिम में जबकी पत्नी के जाने पर दूसरे के कहने पर शक की दृश्टिकोण से देखता है इसका उल्टा भी होता है और बाद में अंदरूनी मनमुटाव हो जाता है जों ठीक नहीं है आपस में प्रेम से रहें और एक संस्कार को बचाये रखें जों हमारे पूर्वजों ने काफी तप कर दिया है अत: उसे बनाए रखें यदि तकलीफ है तो बातें कर समस्या का हल निकालने की कोशिश करें एक बार मैं हरिद्वार शांतिकुंज में गया और वहाँ फुलपैंट पहना था लेकिन वहाँ हवन करने हेतु धोती पहनना पड़ा लेकिन ऐ गुरु का आश्रम है अत: हम उसमें उनके नियम की अवहेलना नहीं कर सकते इसका जरूर कोई अध्यात्मिक कारण होगा भारत में हमेशा नारी को पूजन किया है उनके अच्छे संस्कार और उनके त्याग और बलिदान के कारण और इसलिए हमारी भारत माता का आशीर्वाद है कि हम सभी मिलकर रहते है अत: जीवन में सबका अपना धर्म है जिसे निभाना चाहिए ऐ सभी के लिए बराबर हो, समानता का अधिकार होना चाहिए और साथ मिलकर एक अच्छा नागरिक बनना ही द्ध कर्तव्य है जिसमें पग पग पर कांटे भी आएंगे लेकिन आप उसमें अच्छा बनकर निकलोगे.यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका कर्तव्य है कि उसे सफलता पूर्वक करें जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा छुट्टी के दिनों में ईश्वर का ध्यान करें क्योंकि यही सबसे सही वक़्त होता है उसे जानने की इसमें किसी को बुरा लगता है तो लगने दीजिये ईश्वर आपको ऐसा बना देगा कि किसी भी संकट में आपको मदद करेगा लोग क्या बोलते हैं इसपर जाने की जरुरत नहीं है जहाँ तक सेहत का सवाल है ईश्वर ही साथ देने वाला है और डरने की बिलकुल जरुरत नहीं है क्योंकि ईश्वर की आराधना से आपको क़ोई छू भी नहीं सकेगा और घर की छोड़िये बाहर लोग आपको अच्छा मानते हैं तो आप सही हैं खत्म हो जाता एक दिन यह जवान शरीर लेकिन आप सही होंगे तो मौत से डर नहीं लगेगा बल्कि प्रेम हो जायेगा महा कुम्भ में मैं किसी कारणवश नहीं जा सका लेकिन यदि मैं अच्छा इंसान हूँ तो पाप और पुण्य आपके कर्म से प्राप्त होता है क्योंकि अगर आप अच्छे होंगे तो आपपर लोग ज्यादा भरोसा करेंगे क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है उसे मालूम है र्त कौन है अत:रावण से माता सीता को बचाने के लिए भगवान लक्षमन ने एक रेखा खींची थी जिसे रावण ने धोखे से पार करवा दिया और माता सीता को रावण ने अशोक वाटिका में कैद कर लिया अत: भगवान राम ही थे जो रावण जैसा महाशक्ति को उसके अहंकार को उस अमृत को भी सूखा कर उसका नाश कर दिया ऐ थी उनकी उस समय की मर्यादा बाद में जब गद्दी मिली तो प्रजा को सर्वोपरि माना और एक प्रजा को माता सीता पर गलत आरोप के कारण त्याग दिया क्योंकि उस समय उनका धर्म था प्रजा के हितों को ध्यान देना जिससे ऐ दर्शाता है कि परिवार की राजनीती नहीं की और माता सीता ने भी इसे सहर्ष स्वीकार किया अत: कागजी शेर से अच्छा है राम भक्त बनना और मर्यादा का पालन करना नर नारी एक समान है सभी अपने अपने कर्मों करने के लिए उतरदाई हैं जिसे आपसी सहमति से ही हल किया जा सकता है यदि लगता है वो गलत है और मैं सही हूँ तो आँखे बन्द कीजिये और कुछ छन के लिए कोई उत्तर ना दे ईश्वर का ध्यान दे और एक कदम आप पीछे हटे और वो भी ताकि संतुलन बना रहें लेकिन बार बार ऐसा हो रहा तो किसी के जिद पर अगर ऐसा होता है तो आप अपनी जिंदगी को बोझ क्यों लेते हैं क्योंकि ऐ आपके इतना व्याकुल कर देगा कि आप आत्महत्या की ओर अग्रसर करेंगी और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जवानी खत्म होने के बाद जब बूढ़े होंगे तो मदद के लिए क़ोई साथ नहीं आएगा और छोड़ दीजिये मोह माया भगवान श्री राम के चरणों में गिरकर मन में प्रभु को बसा लीजिये आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और सत्य का पता अपने आप लग जाएगा क्योंकि राम नाम ही सत्य है भगवान को जंगल में निचे ही सोना पड़ा लेकिन हिम्मत नहीं हारें ना तो किसी से कुछ लिए और शबूरी के जूठे बैर भी खा गए और केवटराज को सोने की अंगूठी भी माता सीता ने उनके नाव से चढ़ने के बाद दि. अत: हमेशा हमें परिवार को मिला कर माता पिता को साथ लेकर चलना चाहिए।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

संपादकीय

भीतर के दुश्मन

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बीच कुछ देश विरोधी तत्वों का पर्दाफाश होना चौंकाता है कि कैसे कुछ लोग पैसे व शानोशौकत के लालच में देश की सुरक्षा व लोगों का जीवन भी दांव पर लगा देते हैं। देश के भीतर ये दुश्मन बेहद घातक हैं। पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई से ताल्लुक रखने पर पिछले दिनों हरियाणा, पंजाब व यूपी के कुछ लोगों की गिरफ्तारी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये एक गंभीर चुनौती है और हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों और खुफिया संस्थाओं को अब इस चुनौती को गंभीरता से लेना होगा। ये तत्व न केवल जासूसी में लिप्त थे बल्कि भारत विरोधी प्रचार का भी हिस्सा थे। जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव को भी खतरे में डाल सकते हैं। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा की रहने वाली सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ज्योति कथित तौर पर हाल के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी के संपर्क में थी, जिसे हाल ही में भारत विरोधी गतिविधियों के लिये देश से निकाला गया। इस मामले में चल रही जांच से पता चला है कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले से पहले ज्योति कश्मीर गई और उससे पहले पाकिस्तान गई थी। उस पर पाक के खुफिया अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप हैं। यूपी के रहने वाले शहजाद और नौमान इलाही पर भी इसी तरह के आरोप हैं। पंजाब में मालेरकोटला के दो लोगों को भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों को पता लगाना होगा कि क्या इन आरोपियों की सैन्य या रक्षा अभियानों से संबंधित जानकारी तक सीधी पहुंच थी या वे इसे उच्च पदस्थ स्रोतों से प्राप्त कर रहे थे? रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां ज्योति को एक खुफिया एजेंट के रूप में तैयार कर रही थीं। वह सीमा पार से चलाए जा रहे नेटवर्क का हिस्सा थी। उम्मीद है कि पूछताछ में ऐसे सबूत मिल सकते हैं जो भारत के खिलाफ बड़ी साजिशों का खुलासा कर सके। निस्संदेह, भारत विरोधी शक्तियों के हाथ में खेलकर देश को मुश्किल में डालने का यह कृत्य परेशान करने वाला है। बहुत संभव है कि जासूसी कांड में लिप्त ये भारतीय बड़े आर्थिक प्रलोभनों के लालच में पाक एजेंटों के जाल में फंसे हों। निस्संदेह, इन लोगों की परवरिश में कहीं चूक रही है जो इन्हें यह बोध नहीं करा सकी कि चंद पैसों व सुविधाओं के लालच में देश के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। निश्चय ही यह खुलासा राष्ट्रघाती खेल का छोटा हिस्सा है, आने वाले समय में और बड़ी मछलियां इस दलदल में पकड़ी जा सकेंगी। आने वाले वक्त में कई ऐसे जासूसों का खुलासा हो सकता है, जो आतंकवादियों को भारत की धरती पर हमला करने का इनपुट दे रहे हों। केंद्र व राज्य सरकारों, मीडिया और जनता को मिलकर ऐसे तत्वों को बेनकाब करने में मदद करनी चाहिए ताकि देश मे छुपी इन काली भेड़ों को बाहर किया जा सके। एक छलकपट वाले सूचना युद्ध के माध्यम से देश को नुकसान पहुंचाने की आईएसआई की साजिश को सख्ती से नाकाम किया जाए। विडंबना है कि पाकिस्तान भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत फायदा उठा रहा है। वह सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ज्योति का इस्तेमाल न केवल जासूसी के लिये कर रहा था बल्कि भारत के खिलाफ प्रचार तथा पाक की छवि को सुधारने के लिये भी कर रहा था। ज्योति पर आरोप है कि वह सोशल मीडिया के जरिये पाक की उजली छवि गढ़ रही थी। आरोप ये भी कि उसकी एक पाक खुफिया अधिकारी से अंतरंगता रही है, जिसके साथ वह बाली घूमने भी गई थी। पाक दूतावास की एक पार्टी के वीडियो में भी वह नजर आई है।

सेना की वर्दी पर राजनीति की छींटाकशी!

(लेखिका- सोनम लववंशी)

सियासत अब बयानबाज़ी की रस्साकशी में उलझी वह बेतुकी नुमाइश बन गई है, जहाँ तर्क, गरिमा और शालीनता का वध सार्वजनिक मंचों पर खुलेआम होता है और तालियाँ बजती हैं, जैसे कोई हास्य का प्रहसन चल रहा हो। मध्यप्रदेश सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री एवं भोपाल गैस त्रासदी व लोक परिसंपत्ति मंत्री विजय शाह ने हाल ही में महू में ऐसा ही एक राजनीतिक तमाशा पेश किया जिसमें न सेना की गरिमा बची, न महिलाओं की मर्यादा, न संविधान की आत्मा। उन्होंने मंच से गरजते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को जवाब देने के लिए उनकी बहन को भेजा। ज़रा रुकिए, सोचिए, यह मंत्री हैं। यह वही मंत्रालय है, जहाँ से हमें उम्मीद होती है कि आदिवासी समाज के संवेदनशील मुद्दों पर शालीन, जागरूक और विचारशील नेतृत्व मिलेगा। लेकिन जब वही कुर्सी किसी 'जुबानी जिहाद' के योद्धा के हवाले हो जाए, तो मंत्रालय की गरिमा भी बयानबाज़ी की भेंट चढ़ जाती है। बयान सुनकर पहले तो लगा कि शायद मंत्रीजी ने किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ ली है, लेकिन फिर समझ आया कि यह तो राष्ट्रवाद का नया संस्करण है, जिसमें बहादुर महिला सैन्य अधिकारी को भी लिंग के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। क्या सेना की कोई महिला अधिकारी अब एक 'प्रतिशोध की बहन' बनकर परोसी जाएगी? क्या उसका पराक्रम, उसकी वर्दी, उसका प्रशिक्षण सब केवल इसीलिए था कि उसे एक पुरुषवादी राजनीतिक कल्पना का औज़ार बना दिया जाए? यह बयान न सिर्फ अशालीन है, बल्कि सैन्य मर्यादाओं का मखौल उड़ाने वाला भी है। क्या मंत्रीजी को यह ज्ञान है कि सेना का हर अभियान गोपनीय रणनीति, अनुशासन और प्रशिक्षण की उपज होता है, न कि घरेलू झगड़े की तरह फकिसकी बहन किसके घर गईफ वाले मौहल्ले के विमर्श पर आधारित? और यदि उनकी भाषा इतनी ही 'वीर रस' में डूबी हुई है, तो उन्हें संस्कृति मंत्री क्यों नहीं बना दिया जाता, जहाँ वे महाभारत और रामायण की पुनर्रचना कर सकें?

इस देश में नारी को देवी का रूप कहा जाता है, लेकिन जब वही महिला किसी पद या शक्ति की भूमिका में आती है, तो उसके अस्तित्व को भी उसके लिंग से जोड़कर ही परिभाषित किया जाता है। विजय शाह का बयान इस विकृति की जीवंत मिसाल है। उन्होंने सेना की महिला अधिकारी को न सिर्फ 'किसी की बहन' कहा, बल्कि उसे 'यौनिक प्रतीक' के तौर पर इस्तेमाल किया, जिससे बदला लिया गया। यह सिर्फ अश्लीलता नहीं, यह वैचारिक दरिद्रता है। और सबसे विडंबनापूर्ण बात यह है कि यह सब उस व्यक्ति ने कहा है जो राज्य सरकार का एक जिम्मेदार मंत्री है। लेकिन असली सवाल सिर्फ मंत्री की जुबान का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का है जो ऐसी जुबानों को बढ़ावा देती है। ऐसे वक्तव्यों पर पार्टी की ओर से कोई सार्वजनिक आलोचना नहीं होती। कोई नेता मंच से यह नहीं कहता कि फशब्द वापस लो, यह मर्यादा नहीं फ क्या यह चुप्पी संकेत है कि ये विचार पार्टी के भीतर स्वीकार्य हैं? या फिर हम अब उस दौर में आ गए हैं जहाँ विचारधारा की लड़ाई नहीं, बयानबाज़ी की प्रतियोगिता चल रही है? सोचिए, कर्नल सोफिया जैसी अधिकारी जिन्होंने अपनी काबिलियत से सेना में स्थान पाया, अब एक राजनीतिक बयान में सिर्फ किसी की बहन बनकर रह जाएँ, तो क्या यह उस 'न्यू इंडिया' का चेहरा है जिसे हम गर्व से देखते हैं? क्या स्त्री सशक्तिकरण अब केवल नारे बनकर रह जाएंगे, और मंच पर 'नग्न प्रतिशोध' के कल्पना-चित्रों से जनता का मनोरंजन होगा? राजनीति अब विचारों की लड़ाई नहीं रही। अब यह शब्दों की तलवारबाज़ी बन गई है, जिसमें जितनी भड़काऊ भाषा, उतनी तालियाँ। विजय शाह ने कोई चूक नहीं की उन्होंने पूरी तैयारी से बोला। और उनके शब्द सिर्फ उन्हें नहीं, पूरी व्यवस्था को बेनकाब करते हैं। बयानबाज़ी का यह खेल लोकतंत्र को धीरे-धीरे एक हास्य-व्यंग्य में बदल रहा है, जहाँ हर गंभीर बात भी तमाशा बनकर रह जाती है। जब नेतृत्व भाषा की गरिमा नहीं संभाल सकता, तब जनता को खुद तय करना होगा कि वोट बयान वीरों को देना है या ज़िम्मेदार प्रतिनिधियों को। नहीं तो आने वाले कल में शायद संसद भी किसी स्टैंडअप कॉमेडी शो का विस्तार लगने लगे। और तब हमें कोई बताएगा कि हमने 'उनकी बहन' से बदला लिया मगर यह नहीं बताएगा कि हमारी चेतना कब की मारी जा चुकी है।

(चिंतन-मनन)

चिंतन मनन

गतिशील रहें

एक यात्री जा रहा था। अंधेरी रात थी। उसे लम्बा रास्ता तय करना था। एक व्यक्ति ने उसे लालटेन देते हुए कहा, इसके प्रकाश में तुम अपना रास्ता देख पाओगे। मार्ग सुख से कटेगा। इसे ले जाओ। उस यात्री ने देखा कि लालटेन का प्रकाश तीन-चार फीट तक फैल रहा है। उसके मन में संदेह हुआ कि रास्ता बहुत लंबा है। प्रकाश केवल तीन-चार फीट तक ही पड़ता है। रास्ता पार कैसे कर पाऊंगा? वह उलझ गया और उलझता ही गया। वह बोला, तीन-चार फीट का प्रकाश मुझे दस मील की यात्रा कैसे करा पाएगा?

यह विधि को न समझने के कारण है। विधि को समझे बिना साधक उलझ जाते हैं। विधि को ठीक समझ लेते हैं तो तीन-चार फीट का प्रकाश दस मील की यात्रा करा सकता है। यह प्रकाश दस मील के पूरे पथ को प्रकाशित कर सकता है। आप चलते चलें, दस मील का रास्ता प्रकाशित हो जाएगा और यदि उसी बिन्दु पर खड़े रह गए तो दो फीट का रास्ता ही प्रकाशित होगा, शेष अंधकार ही अंधकार रहेगा। आवश्यकता है चलने की, सतत गतिशील रहने की।

विधि को समझें और चलें। विधि को समझना ही पर्याप्त नहीं है, चलना भी पड़ेगा। आगे से आगे बढ़ना होगा। यदि नहीं चले, रूके रह गए तो प्रकाश जहां पड़ता है वहीं पड़ेगा, वह आगे नहीं बढ़ेगा। वह तभी बढ़ेगा, जब हम बढ़ेंगे। वह हमारे रूकने के साथ रूकेगा और बढ़ने के साथ बढ़ेगा। अभ्यास करते जाएं। आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मंजिल स्वत- मिल जाएगी।

विचार मंथन

परमाणु बिजली: विदेशी दबाव में आत्मघाती निर्णय

(लेखक- सनत जैन)

मध्य प्रदेश की भोपाल गैस त्रासदी को आखिर दुनियां कैसे भूल सकती है। तब यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इसमें हजारों लोगों की जान चली गई और लाखों लोग प्रभावित हुए। आज भी इस भयानक औद्योगिक त्रासदी को याद कर लोग सिहर उठते हैं। इस त्रासदी के अवशेष आज भी लोगों को परेशान किए हुए हैं। इस भयावह घटना से सबक लेते हुए बाद की सरकारों ने कभी कोई ऐसे औद्योगिक संयंत्र या उसकी इकाई को विदेशी दबाव में लगाने या शुरु करने की इजाजत नहीं दी, जिससे दोबारा इस तरह की कोई त्रासदी सामने आए। समय व्यतीत होने के साथ वर्तमान सरकार शायद इसे भूल गई। यही वजह है कि अब परमाणु बिजली जैसे निर्णय लेने पर वह मजबूर है। ईश्वर न करे कि आने वाले समय में फिर यह दिन भारत के लोकतांत्रिक और जनहितकारी इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाए। दरअसल भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों के दबाव में आकर जो नया फैसला लिया है, वह देश की सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिकों के जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इस अंदेशे के साथ यह भी रेखांकित किया जा रहा है कि सरकार ने परमाणु बिजली संयंत्रों में दुर्घटना की स्थिति में विदेशी कंपनियों को मुआवजे की जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। अब यदि कोई परमाणु हादसा होता है, तो उसका पूरा भार सरकारी कंपनी और भारतीय करदाताओं के ऊपर पड़ेगा। यहां बताते चलें कि 2010 में पारित सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के अनुसार, परमाणु संयंत्र ऑपरेटर को 1500 करोड़ और सरकार को 1100 करोड़ रुपये तक मुआवजे की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि यह राशि भी किसी गंभीर परमाणु दुर्घटना के लिए बेहद कम थी। 2011 के फुकुशिमा हादसे में जापान को 16 लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च उठाना पड़ा था। बावजूद इसके, अब सरकार ने कंपनियों को पूरी तरह जिम्मेदारी से मुक्त कर, भारतीय नागरिकों को जोखिम में डालने वाला कदम उठाया है।

भारत में पहले से ही 23 परमाणु संयंत्र कार्यरत हैं, जो सरकारी निगरानी में चलते हैं। परंतु अब अमेरिका, फ्रांस और रूस की पुरानी तकनीक को भारत में डंपिंग ग्राउंड की तरह उतारा जा रहा है। ये कंपनियां भारत को एक बाजार की तरह देख रही हैं, जहां सुरक्षा और जवाबदेही की अनदेखी कर मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। जयतापुर और कुडनकुलम जैसे भूकंप संभावित क्षेत्रों में संयंत्र स्थापित करना एक खतरनाक प्रयोग है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे चिंता की बात यह है कि सरकार ने यह फैसला बिना संसद में चर्चा के, जनता को अंधेरे में रखकर लिया है। पोस्ट फैक्टो क्लीयरेंस जैसे नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसमें पर्यावरणीय अनुमति संयंत्र स्थापित होने के बाद ली जाती है। यह व्यवस्था पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को समाप्त करती है। परमाणु ऊर्जा की आर्थिक तर्कसंगतता भी सवालों के घेरे में है। जहां सौर ऊर्जा 2 से 3.5 रुपये प्रति यूनिट और कोयला आधारित बिजली 4 से 6 रुपये में उपलब्ध है, वहीं परमाणु बिजली की लागत 9 से 12 रुपये प्रति यूनिट तक होती है। संयंत्र निर्माण में 10 से 15 वर्ष लगते हैं, जबकि सौर या थर्मल संयंत्र 1 से 2 साल में तैयार हो जाते हैं। इसमें पर्यावरणीय खतरा भी कम नहीं है। परमाणु कचरे को निष्प्रभावी करने में हजारों वर्ष लगते हैं, और यह जमीन, जल और समुद्री जीवन को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाता है। जब दुनिया के देश—जर्मनी, जापान और इटली—परमाणु ऊर्जा से दूरी बना रहे हैं, भारत में इसके विस्तार को जनविरोधी और आत्मघाती नीति माना जा रहा है। भारत सरकार को चाहिए कि वह जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता दे, और विदेशी दबाव के बजाय वैज्ञानिक विवेक और लोकहित को ध्यान में रखकर निर्णय ले। देश विकास करे लेकिन विकास के नाम पर आत्मघाती कदम उठाए जाएं कहां तक उचित है?

भारत में जल्द सेवा देने लगेगी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक

मुंबई।

एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट से जुड़ी इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए दूरसंचार विभाग (डॉट) ने लेटर ऑफ इंटेंट (एलओई) जारी किया था। कंपनी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सभी जरूरी लाइसेंस शर्तों को मानने पर सहमति देने के बाद अब जल्द ही अंतिम नियामकीय मंजूरी मिलने वाली है। अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) के तहत काम करने वाली नोडल एजेंसी आने वाले दिनों में स्टारलिंक को सैटकॉम सेवाओं की शुरुआत के लिए हरी झंडी दे सकती है।

सूत्रों ने बताया कि इन-स्पेस की अंतर-मंत्रालयी स्थायी समिति अपनी आगामी बैठक में स्टारलिंक के प्रस्ताव पर विचार करेगी। समिति में अंतरिक्ष विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दूरसंचार विभाग (डॉट), गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। भारत में अपनी सेवाओं के वितरण और नेटवर्क विस्तार के लिए रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। इसका मुख्य फोकस ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना है।

सूत्रों ने बताया कि गृह और विदेश मंत्रालय, जो सुरक्षा और भू-राजनीतिक मामलों में अंतिम निर्णय लेने वाले प्रमुख मंत्रालय हैं, ने पहले ही स्टारलिंक के प्रस्ताव को दूरसंचार विभाग के स्तर पर मंजूरी दे दी है। इसलिए अब इन-स्पेस की ओर से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। स्टारलिंक को 7 मई को डॉट की ओर से 'ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (जीएमपीसीएस)' लाइसेंस के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किया था। इसका मतलब यह है कि सुरक्षा और रणनीतिक चिंताओं का समाधान कंपनी ने कर दिया है और संबंधित एजेंसियों ने सत्यापित भी कर लिया है।

मोदी सरकार ने अब सैटकॉम कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें जियो और एयरटेल जैसे भारतीय टेलीकॉम दिग्गजों की सैटकॉम यूनिट्स और संयुक्त उपक्रम भी शामिल हैं। स्टारलिंक के भारत में आने से देश के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड

इंटरनेट पहुंचने की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं।

पहलगाम हमला कनेक्शनः तीन दिन में अहमदाबाद के 8 हजार घरों पर दौड़ेंगे 50 बुलडोजर

अहमदाबाद।

पहलगाम हमले के बाद गुजरात में बांग्लादेशियों की पहचान और फिर बड़ी संख्या में यहां घुसपैठियों के पकड़े जाने के बाद अप्रैल के अंत में नगर निगम ने बुलडोजर ऐक्शन की शुरुआत की थी। तब 1.5 लाख वर्ग मीटर जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया था तो अब यहां कुल 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। अब अहमदाबाद में एक बार फिर 50 से ज्यादा बुलडोजर दौड़ रहे हैं। चंदोला झील के किनारे बसाए गए मोहल्लों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तीन दिन में यहां करीब 8000 घरों और अन्य ढांचों को तोड़ा जाएगा। मंगलवार सुबह से ही चंदोला इलाके में दर्जनों बुलडोजर चलने लगे। विरोध की आशंका को देखते हुए 3000 पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया है। नगर निगम के अलावा पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अहमदाबाद के डीसीपी रवि मोहन सैनी ने कहा, चंदोला इलाके से अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। एसआरपी की 25 कंपनियां और 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इस इलाके के सभी निर्माण अवैध हैं और सबको हटाया जा रहा है।इससे पहले 29 और 30 अप्रैल को बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण किया गया था। इसकी शुरुआत तब की गई जब इन बस्तियों से बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया था। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद अहमदाबाद पुलिस ने 26 अप्रैल को चंदोला झील क्षेत्र में छापा मारा और लालू पठान उर्फ लल्लू बिहारी की मदद से क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे 150 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। चंदोला झील में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के पीछे के 'मास्टरमाइंड'लालू पठान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पठान ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को किराये का मकान दिलाने और आधार कार्ड प्राप्त करने में भी मदद की थी। अधिकारियों ने बताया कि अवैध रूप से निर्मित लगभग हजारों मकान, झोपड़ियां और अन्य संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए चिह्नित किया गया है। अप्रैल में हुई कार्रवाई में अतिक्रमण हटाने के लिए 70 से अधिक 'अर्थमूवर'मशीनें और 200 'डंपर'लगाए थे।

भारत-तुर्की के बीच व्यापार करीब 10.43 अरब डॉलर का, अब हो रहा नुकसान

पाक का समर्थन करने पर तुर्की के सेब-मार्बल का हो रहा बहिष्कार

नई दिल्ली।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को फिर बढ़ा दिया। इसके बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। भारतीय वायुसेना ने इस कार्रवाई में स्वदेशी हथियारों जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम का उपयोग किया और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की रक्षा क्षमता और ÷मेड इन इंडिया÷ हथियारों की सफलता का उदाहरण बताया। इस सैन्य कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान ने तुर्की से प्राप्त सैकड़ों ड्रोन जैसे बायरकटर टीबी2 और अस्सिगार्ड सोंगर का इस्तेमाल कर भारत पर हमला करने की कोशिश की, जिसे भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया। भारत ने इसके जवाब में ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में तुर्की की भूमिका सामने आने के बाद भारत में उसके प्रति गुस्सा और आक्रोश और अधिक गहरा गया। तुर्की द्वारा पाकिस्तान को सैन्य समर्थन देने और ड्रोन आपूर्ति करने की खबरों के चलते भारत में 'बॉयकॉट तुर्की' अभियान शुरू हुआ, जिसने सोशल मीडिया से लेकर व्यापार और पर्यटन तक प्रभाव डाला। व्यापार की दृष्टि से भारत और तुर्की के बीच कुल व्यापार लगभग 10.43 अरब डॉलर का है। भारत तुर्की को खनिज ईंधन, कपास, इंजीनियरिंग सामान, रसायन और एल्यूमीनियम जैसे उत्पाद निर्यात करता है, जबकि तुर्की से संगमरमर, सेब, पेट्रोलियम उत्पाद, सोना, मोती और अकार्बनिक रसायन आयात करता है। अब 'बॉयकॉट तुर्की' के चलते उदयपुर के मार्बल कारोबारियों ने तुर्की से आयात बंद करने का फैसला लिया है, जिससे करीब 3,000 करोड़ रुपये के कारोबार पर असर पड़ेगा। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था तुर्की पर निर्भर नहीं है और सरकार ने वैकल्पिक स्रोतों जैसे न्यूजीलैंड (सेब) और इटली (मार्बल) की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की विदेश नीति, रक्षा रणनीति और आर्थिक आत्मनिर्भरता को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है।

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद अब विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में जुटी मोदी सरकार

नई दिल्ली।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' कर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों तहस नहस कर स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। हालांकि, कार्रवाई के बाद भारत ने संघर्ष को सीमित रखकर एक परिपक्व और जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका निभाई। मोदी सरकार का उद्देश्य न केवल आतंकी ताकतों को जवाब देना था, बल्कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को भी ध्यान में रखना था।

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित विकसित भारत 2047 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब भारत को अपनी आर्थिक और सामाजिक क्षमता को तेज़ी से विकसित करना होगा।

निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ानाः वैश्विक 32 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी अभी मात्र 2 प्रतिशत है। इस 4 प्रतिशत तक ले जाना संभव है, विशेषकर सेवा क्षेत्रों में जहां पहले से भारत की पकड़ है।

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धिः विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने के लिए भारत को प्रति व्यक्ति आय को करीब 13,000 डॉलर तक पहुंचाना होगा। फिलहाल यह करीब 2,500 डॉलर है। इसके लिए हर साल 7.6 प्रतिशत से अधिक की जीडीपी वृद्धि जरूरी है। अनुमान है कि 2047 तक भारत की आबादी 1.6 से 1.7 अरब तक पहुंच सकती है। इतनी बड़ी आबादी को उत्पादक संसाधन में बदलना भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होगी।

शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सुधारस्थायी विकास और रोजगार सृजन के लिए इन तीन क्षेत्रों में भारी निवेश और नीति सुधारों की आवश्यकता है।

भारत अब केवल आतंक का जवाब देने वाले देश के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व क्षमता वाले राष्ट्र के रूप में खुद को प्रस्तुत कर रहा है। चाहे तकनीक हो, रक्षा, अंतरिक्ष या डिजिटल सेवाएं – भारत हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। ने कहा कि वह माफी मांग चुके हैं और माफी का वीडियो भी जारी कर चुके हैं।

अमित मालवीय का पोस्ट वायरल, पाकिस्तान की भाषा बोले रहे राहुल गांधी

नई दिल्ली।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी चल रहीं हैं। इसी बयानबाजी के बीच भाजपा नेता अमित मालवीय ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके समर्थकों की भाषा बोल रहे हैं। मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री को बधाई नहीं दी। इसके बजाय वह बार-बार यह सवाल उठा रहे हैं कि भारत ने कितने फाइटर जेट खोए, जबकि इस सवाल का जवाब डीजीएमओ की ब्रीफिंग में पहले ही दिया जा चुका है। मालवीय ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने एक बार भी यह नहीं पूछा कि इस संघर्ष में कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए गए या भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला कर कितने जेट नष्ट किए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी का अगला कदम पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान 'निशान-ए-पाकिस्तान' लेना होगा?

मालवीय का यह बयान राहुल गांधी के हालिया बयानों के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के नुकसान पर सवाल उठाए थे। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी की यह टिप्पणी देश की सेना और सरकार की सफलता को कमतर करने की कोशिश है। ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सैन्य ताकत और रणनीतिक सफलता का प्रतीक माना जा रहा है। इस विवाद ने एक बार फिर

राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ैर उसके कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दागे, जिनमें आतंकवादी समूह लश्कर-ए-मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर भी शामिल है। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ काफी सख्त कदम उठाए थे और पीएम मोदी लगातार आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की बात कर रहे थे।

सिविल जज के लिए 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य

शीर्ष अदालत ने सीधे चयन की व्यवस्था को आखिर क्यों किया खत्म

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवाओं में प्रवेश को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की भर्ती के लिए न्यूनतम तीन साल की वकालत की प्रैक्टिस अनिवार्य होगी। शीर्ष अदालत ने लॉ ग्रेजुएट्स के सीधे चयन की व्यवस्था को खत्म करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायिक सेवाओं में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए व्यावहारिक अनुभव बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की त्रिपल बैंच ने यह निर्णय सुनाया। फैसले में कहा गया है कि उम्मीदवारों को वकील के रूप में कम से कम तीन वर्षों तक प्रैक्टिस करनी होगी और यह अवधि प्रोविजनल नामांकन की तिथि से मानी जाएगी। हालांकि, यह नियम केवल भविष्य की भर्तियों पर लागू होगा और पहले से चल रही प्रक्रियाओं पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहम बातें-

लॉ ग्रेजुएट्स के सीधे चयन की प्रक्रिया समाप्त। तीन साल की न्यूनतम कानूनी प्रैक्टिस आवश्यक। अनुभव की गिनती प्रोविजनल नामांकन से होगी। 10 साल का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ वकील से प्रमाणन जरूरी। सभी राज्यों को अपने सेवा नियमों में संशोधन के निर्देश। इसके साथ ही सिविल जज सीनियर डिवीजन में त्वरित पदोन्नति के लिए 10 प्रतिशत कोटा आरक्षित होगा। न्यायिक लिपिक के रूप में अनुभव को भी माना जाएगा। सीजेआई गवई ने अपनी टिप्पणी

में कहा कि किताबी ज्ञान से न्याय नहीं हो सकता। न्यायालय को समझने और वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेकर ही एक अच्छा न्यायाधीश तैयार होता है। नए स्नातकों की नियुक्ति से कई व्यवहारिक समस्याएं सामने आई हैं। इसलिए, परीक्षा से पहले न्यूनतम अभ्यास आवश्यक है। इस फैसले का सीधा असर देशभर के लॉ स्नातकों पर पड़ेगा। अब सीधे कॉलेज से निकलकर जज बनने का रास्ता बंद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य सरकारें और उच्च न्यायालय जल्द ही अपने-अपने भर्ती नियमों में संशोधन करेंगी।

अमेरिका में गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने पर जोर देगा भारत

द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ चल रही वार्ता

नई दिल्ली।

भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ चल रही बातचीत में भारतीय निर्यातकों की खातिर अमेरिका में गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने पर जोर देगा। मीडिया रिपोर्ट में एक सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका के पास गैर-शुल्क बाधाओं की लंबी सूची है जिस पर वह भारत के साथ चर्चा करना चाहता है। हालांकि अमेरिका जीवन एवं स्वास्थ्य जैसे गैर-शुल्क उपायों पर चर्चा के लिए राजी नहीं है।

रिपोर्ट में अधिकारी ने कहा कि उद्योग ने अमेरिका में निर्यात बढ़ाने में प्रमुख बाधाओं के रूप में नियामकीय अड़चन और प्रमाणन की उच्च लागत समेत अन्य मुद्दों को उठाया है। उन्होंने कहा कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) से भारतीय फार्मा निर्यातकों के लिए उत्पाद की मंजूरी की लागत 9,280 से 5,40,00 डॉलर के बीच आती है जबकि अमेरिकी निर्यातकों को अपेक्षाकृत कम लागत में भारतीय बाजार तक पहुंच उपलब्ध है। रिपोर्ट में एक अन्य अधिकारी ने बताया कि भारतीय फार्मा निर्यातकों के लिए अमेरिका में प्रमाणपत्र हासिल करने में काफी समय लगता है। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों को प्रमाणन जारी करने के लिए एफडीए अधिकारियों के फील्ड विजिट का खर्च उठाना पड़ता है जो गैर-शुल्क बाधा है।

रिपोर्ट में एक अन्य पूर्व व्यापार अधिकारी ने कहा कि अक्सर गैर-शुल्क बाधाएं और गैर-शुल्क उपाय के बीच बारीक रेखा होती है। विनियमन ठीक हैं लेकिन इसकी व्याख्या के हिसाब से समस्या आ सकती है। हम अमेरिका को बता रहे हैं कि उनके सुरक्षा और डंपिंग विरोधी शुल्क लगातार बढ़ रहे हैं और अस्थायी व्यापार सुरक्षा उपाय एक तरह से स्थायी बन रहे हैं। इस पर हमारे उनके साथ मतभेद हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने 2022 में 'भारतीय निर्यातकों के समक्ष अपने शीर्ष साझेदार सदस्यों से आने वाली गैर-टैरिफ बाधाएं' शीर्षक वाले कार्य पत्र में कहा था

कि कृषि उत्पादों के उत्पादन और व्यापार में कीटनाशकों से संबंधित मुद्दे और अनुचित और सख्त लेबलिंग एवं पैकेजिंग आवश्यकताओं की वजह से भारत के खाद्य उत्पादों का निर्यात प्रभावित होता है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस समय अमेरिका में व्यापार वार्ताकारों की एक टीम का नेतृत्व कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द व्यापार समझौता किया जा सके। गोयल वाशिंगटन में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि और अमेरिकी वाणिज्य सचिव से मिलने वाले हैं।

8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट जानिए अब कितनी बढ़ सकती है सरकारी बाबुओं की सैलरी

नई दिल्ली।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग का इंतजार है। करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और करीब 68 लाख पेंशनर्स इस खुशखबरी को सुनने के लिए बेताब है।

साथ ही, उनमें इस बात की भी जिज्ञासा इस वक्त बनी हुई है कि उनकी कितनी सैलरी बढ़ेगी, क्या कुछ फिटमैंट फैक्टर रहेगा और कब से ये सबकुछ लागू होगा। हर दस साल में लगने वाले पे कमीशन से सरकारी बाबुओं के वेतन में अच्छा खास इजाफा हो जाता है। साथ ही, उनकी पेंशन और डीए में भी बढ़ोतरी होती है। जहां तक इसके लागू होने की बात है तो यह 2026 में यानी अगले साल से लागू हो जाएगा। हालांकि, अभी तक इस बारे में सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर एलान नहीं किया है।

आठवें वेतन आयोग को लागू होने में देरी हो सकती है और सरकार इसे 2026 में एक अप्रैल से लागू कर सकती है। 2025 के दिसंबर में सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार सरकारी बाबुओं की सैलरी वेशेष फिटमेंट फैक्टर के ऊपर आधारित होगी। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सातवें वेतन आयोग के दौरान 2.576 का फिटमेंट फैक्टर लगाया गया था, लेकिन आठवें वेतन आयोग में सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लगा सकती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सरकार आठवें वेतन आयोग में 1.92 के फैक्टर पर विचार कर सकती है।

इन सब लिहाज से अगर सैलरी को कैलकुलेट किया जाए तो अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर 3 या फिर उससे ज्यादा लगाती है तो इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में न्यूनतम 19 हजार रुपये तक का इजाफा हो सकता है और उनका कम से कम सैलरी 51 हजार रुपये से ऊपर हो सकती है। जबकि न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 25 हजार से ज्यादा हो सकती है।

संक्षिप्त समाचार

चुनावी साल में बिहार में 36 अधिकारियों का तबादला

पटना।

बिहार विधानसभा चुनाव इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर में हो सकते है। इस लेकर प्रदेश में जहां राजनीतिक स्तर पर गहमागहमी है, वहीं बिहार में प्रशासनिक स्तर पर भी काफी हलचल है। चुनावी वर्ष में फिर बिहार सरकार ने प्रशासनिक सेवा के 36 अधिकारियों का तबादला किया है। बिहार सरकार ने 36 एसडीओ, एसडीएम और कई डीडीसी का तबादला किया है। जबकि कई सीनियर डिप्टी कलेक्टर को एसडीएम के पद पर पदस्थापित किया है।

हरदोई में राजधानी और काठगोदाम एक्सप्रेस को डी-रेल करने की कोशिश, पुलिस जांच में जुटी

हरदोई।

कुछ उपद्रवी देश में काफी समय से कुछ न कुछ साजिशें रच रहे हैं ताकि भारतीय रेलवे को बड़ा नुकसान पहुंचा सके। बीते कई महीनों में देखा गया कि कई रेल हादसे होते होते बचें हैं। अब ताजा मामला हरदोई से आया है जहां फिर उपद्रवियों ने राजधानी एक्सप्रेस को पटने की साजिश रची थी। हरदोई जिले में लोको पायलटों की सतर्कता के कारण राजधानी एक्सप्रेस सहित दो ट्रेनों को पटरी से उतारने की कोशिश नाकाम कर दी गई। पुलिस ने दावा किया कि अज्ञात बदमाशों ने दलेलनगर और उमरताली स्टेशनों के बीच पटरी पर अर्थिंग वायर का इस्तेमाल कर लकड़ी का गुटखा बांध दिया। पुलिस ने बताया कि दिल्ली से असम के डिब्रूगढ़ जा रही राजधानी एक्सप्रेस के लोको पायलट ने अवरोध को देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगाया। लोको पायलट ने अवरोध को हटाया और रेलवे अधिकारियों को सूचित किया। राजधानी एक्सप्रेस के बाद काठगोदाम एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की दूसरी कोशिश की गई। पुलिस ने बताया कि लोको पायलट की सजगता के कारण घटना टल गई और कोई अनहोनी नहीं हुई।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र निजी भागीदारी बढ़ाने पर विचार कर रही मोदी सरकार

नई दिल्ली। मोदी सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानूनों में संशोधन पर विचार कर रही है। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य पाने के लिए केंद्र सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी सहभागिता बढ़ाना चाहती है। इसके लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कानूनों में बदलाव की जरूरत है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि निजी क्षेत्र को भागीदारी की अनुमति देने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। दरअसल परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं पर जवाबदेही सीमित करने के लिए परमाणु क्षति के लिए जवाबदेही कानून में संशोधन की जरूरत है। केंद्र सरकार नियामक सुधारों पर भी विचार कर रही है और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इनस्पेस) के माडल का मूल्यांकन कर रही है। इनस्पेस अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए नियामक के रूप में कार्य करता है। 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को भी निजी भागीदारी के लिए खोलने की घोषणा की, जिसे अब तक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तक सीमित रखा गया था। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआइएल) देशभर में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन करता है। ये परमाणु संयंत्र देश में 8.7 गीगावाट बिजली का योगदान करते हैं। सीतारमण ने छोटे माड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के अनुसंधान और विकास के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के बजट के साथ परमाणु ऊर्जा मिशन की भी घोषणा की। इसका उद्देश्य 2033 तक पांच स्वदेशी विकसित एसएमआर को क्रियान्वित करना है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा मिशन का उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, नियामक ढांचे को सुव्यवस्थित करना और भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अवरोध साबित हुआ है

भारत ने 2008 में ऐतिहासिक भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु करार के बाद वैश्विक परमाणु व्यापार में सहभागी बनने के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) से छूट प्राप्त की। इसके बाद विदेशी परमाणु ऊर्जा कंपनियों ने भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में रुचि दिखाई है। निजी क्षेत्र के अनुसार ये प्रविधान परमाणु क्षति के पूरक मुआवजे के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौते (सीएससी) के अनुरूप नहीं हैं। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र निवेश करेगा। 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन के इस लक्ष्य में से लगभग 50 प्रतिशत परमाणु ऊर्जा का उत्पादन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) से होने की उम्मीद है।

7 प्रतिष्ठानों से लिए गए सैंपल पाए गए अनसेफ

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम/द्वितीय में प्रस्तुत किये गए प्रकरण

जयपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि सिंह शेखावत ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार लिये गये खाद्य पदार्थों के नमूनों में से अनसेफ पाये गये प्रकरणों में निम्न फर्मों मोहम्मदी पैलेस चांदपोल जयपुर की ग्रेवी, चिकन चंगेजी एवं काली मिर्च, रस्तोगी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर का एमडीएच गरम मसाला, श्याम धणी इंडस्ट्रीज जयपुर का श्याम धणी गरम मसाला, लक्ष्मी स्वीट्स केटर्स सुभाष चौक जयपुर की नमकीन,पेट पूजा होटल महादेव बनीपार्क जयपुर की ग्रेवी, अमरलाल स्वीट्स केटर्स जयपुर के लडडू,लक्ष्मी जोधपुर मिष्ठान भंडार, स्वेज फार्म जयपुर के लड्डू के विरुद्ध प्रकरण मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम/द्वितीय में प्रस्तुत किये जा चुके है।

मोदी के दौरे से पहले भजनलाल सरकार ने अचानक बदले 4 IPS

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 मई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे से पहले भजनलाल सरकार ने चार आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर प्रशासनिक सख्ती का संकेत दिया है। इनमें दो जिलों हनुमानगढ़ और झुंझुनूं में नए पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं, जहां पहले के एसपी को हाल ही में शिकायतों के चलते एपीओ किया गया था।

आदेश के अनुसार आईपीएस लोकेश सोनवाल को झुंझुनूं का पुलिस अधीक्षक (एसपी), हरिशंकर को हनुमानगढ़ का एसपी, और अमित जैन को बालोतरा का एसपी नियुक्त किया गया है। वहीं, शैलेंद्र सिंह इंदोलिया, जो पहले से ही एपीओ (अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर) में थे, को जोधपुर पुलिस आयुक्तालय में उपायुक्त (मुख्यालय और यातायात) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्मिक विभाग ने मंगलवार को इन तबादलों के आदेश जारी किए।

कार्मिक विभाग का आदेश

हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शेखावटी क्षेत्र के सीकर, झुंझुनूं और अन्य इलाकों का दौरा किया था। इस दौरान उन्हें झुंझुनूं और हनुमानगढ़ के तत्कालीन पुलिस अधीक्षकों के कामकाज में खामियों की शिकायतें मिली थीं। इसके बाद दोनों जिलों के एसपी को तुरंत प्रभाव से एपीओ कर दिया गया था। अब इन जिलों में नए अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ताकि कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।

PM मोदी का बीकानेर दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को बीकानेर का दौरा करेंगे। यह 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद उनका पहला राजस्थान दौरा होगा। जानकारी के अनुसार, पीएम सुबह करीब 10.30 बजे बीकानेर पहुंचेंगे और 11 बजे देशनोक के प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद वे पलाना गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें बीकानेर संभाग के विभिन्न जिलों और विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग शामिल होंगे।

विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और बीकानेर-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा, वे 26,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पलाना में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में भी पीएम जनता को संबोधित करेंगे।

हाथों में मेहंदी और टैटू, पत्थरों से हुआ कुचला चेहरा, झाड़ियों में मिला युवती का शव, मचा हड़कंप

उदयपुर। गोगुंदा क्षेत्र के जसवंतगढ़ स्थित आड़ी सड़क पावर हाउस के पास मंगलवार को युवती का शव मिला। प्राथमिक जांच में पता चला की युवती की हत्या कर शव यहां डाला गया है, वहीं पहचान छिपाने के लिए चेहरा पत्थरों से कुचल दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शव को मोर्चरी में रखवाया, वहीं शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। एफएसएल और डॉग स्क्वायड टीम भी साक्ष्य जुटाने में लगी है।

थानाधिकारी श्याम सिंह ने बताया की झाड़ियों में युवती का शव लहूलुहान अवस्था में खून से सना हुआ मिला। चेहरा बुरी तरह से कुचला होने से पहचान में नहीं आ रही। ऐसे संभावना जताई जा रही है कि अज्ञात बदमाशों ने युवती की बेरहमी से हत्याकर शव को झाड़ियों में फेंका और पहचान छिपाने के लिए चेहरे को पत्थरों से कुचल दिया।

पुलिस ने युवती की पहचान के लिए आस-पास के थानों में

फोटो भेजकर गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगालनी शुरू कर दी है। फिलहाल अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

हाथ-पैरों में भी चोटों के निशान

आंख, नाक, मुंह और हाथ-पैर में भी गहरे घाव थे। युवती की उम्र करीब 25 साल के है। दोनों हाथों में मेहंदी लगी थी और बाएं हाथ पर ? का टैटू बना हुआ है।

एक साल पहले भी झाड़ियों में मिला था शव

करीब एक साल पहले भी इसी थाना क्षेत्र के उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे मार्ग पर भादवी गुड़ा के पास एक युवती का शव इसी तरह झाड़ियों में मिला था, जिसकी शिनाख्ती आज तक नहीं हो पाई।

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नया राजस्व गांव रद्द

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वीर तेजाजी नगर को नया राजस्व गांव घोषित करने की राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ ने यह आदेश ग्राम सभा की बैठक में गंभीर प्रक्रियात्मक खामियों को देखते हुए दिया।

याचिकाकर्ता विष्णुदेव चौधरी की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने दलील दी कि जिस ग्राम पंचायत सांगरिया के तहत यह नया गांव बनाया जा रहा था, उसी ग्राम पंचायत से जुड़ी एक अन्य याचिका पहले ही स्वीकार की जा चुकी है। उस मामले में भी ग्राम सभा की बैठक में बैठक का एजेंडा नहीं होना, पर्याप्त कोरम न होना, और बिना सार्वजनिक सूचना के प्रस्ताव पारित किया जाना जैसी कई खामियां पाई गई थी।

कोर्ट ने दिया निर्देश

कोर्ट ने पूर्व याचिका में दिए गए आदेश को वर्तमान मामले पर भी लागू करते हुए 26 जनवरी 2025 को हुई ग्राम सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 1 को रद्द कर दिया। साथ ही 6 अप्रेल 2025 को जारी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया गया।

पीठ ने स्पष्ट किया कि ग्राम सभा की बैठक में जरूरी कोरम नहीं था और न ही प्रस्ताव के लिए कोई पूर्व सूचना जारी की गई थी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि राज्य सरकार भविष्य में नया गांव घोषित करना चाहती है, तो वह कानून सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए ग्राम सभा की वैध बैठक बुला सकती है।

तीसरी बार तैयार हो सकता है निगम का परिसीमन

हाईकोर्ट के आदेश के बाद परिसीमन का नक्शा और ड्राफ्ट दोनों को तीसरी बार नए सिरे से तैयार किया जाएगा। इससे पहले दो बार परिसीमन ड्राफ्ट तैयार कर जयपुर भेजा जा चुका है, लेकिन अब वीर तेजाजी नगर को हटाकर परिसीमन की प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ सकती है। पिछले ड्राफ्ट में पाल गांव (पूर्व) और वीर तेजाजी नगर को मिलाकर वार्ड संख्या 10 बनाया गया था। अब कोर्ट के निर्देश के अनुसार इस वार्ड की संरचना भी बदलनी होगी। निगम को अब परिसीमन की पूरी कवायद दोबारा करनी पड़ेगी।

नहीं पड़ेगा खास असर

इससे अधिकारियों की परिसीमन का ड्राफ्ट और नक्शा तैयार करने की कवायद जरूर दोबारा हो गई है, लेकिन जनसंख्या के तौर पर देखा जाए तो इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। पूर्व में भेजे गए नए परिसीमन में वीर तेजाजी नगर व पूर्वी पाल क्षेत्र को मिलकर बनाए गए वार्ड संख्या 10 में कुल 10749 जनसंख्या ही थी।

वैज्ञानिकों की चेतावनी

समुद्र स्तर बढ़ने से होगा विनाशकारी आंतरिक पलायन

जयपुर। वैज्ञानिकों की एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि पृथ्वी का तापमान सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ता है, तो समुद्र का बढ़ता जलस्तर बेकाबू हो जाएगा और विनाशकारी आंतरिक पलायन शुरू हो सकता है।

यह स्थिति तब भी हो सकती है जब औसत वैश्विक तापमान हाल के वर्षों की तरह 1.2°C बना रहे।

ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें तेजी से पिघल रही हैं – 1990 के दशक से अब तक यह प्रक्रिया चार गुना तेज हो गई है – और यह अब समुद्र के बढ़ते जलस्तर की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है।

वैश्विक तापमान को 1.5°C तक सीमित रखने का अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य अब लगभग असंभव होता जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि अगर कार्बन उत्सर्जन तुरंत घटा भी दिया जाए, तब भी इस सदी के अंत तक समुद्र सालाना 1 सेंटीमीटर की दर से बढ़ेगा – जो कि तटीय सुरक्षा के निर्माण की गति से तेज है।

भविष्य की चिंता

दुनिया फिलहाल 2.5एष्ट से 2.9एष्ट तापमान वृद्धि की दिशा में बढ़ रही है, जो ग्रीनलैंड और पश्चिम अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों के पूरी तरह पिघलने की 'टिपिंग पॉइंट' से आगे होगी। इससे समुद्र का जलस्तर 12 मीटर तक बढ़ सकता

है – जो बेहद गंभीर स्थिति होगी।

जनसंख्या पर असर

आज लगभग 23 करोड़ लोग समुद्र तल से सिर्फ 1 मीटर ऊपर रहते हैं, और 1 अरब लोग 10 मीटर के अंदर। अगर 2050 तक समुद्र का जलस्तर सिर्फ 20 सेंटीमीटर भी बढ़ता है, तो दुनिया के 136 सबसे बड़े तटीय शहरों को हर साल .1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हो सकता है।

हर छोटा कदम मायने रखता है

वैज्ञानिकों ने जोर दिया कि तापमान में थोड़ी सी भी कमी से समुद्र स्तर बढ़ने की रफ्तार कम होती है और तैयारियों के लिए ज्यादा समय मिलता है – जिससे मानवीय पीड़ा कम हो सकती है।

समाधान कठिन, समय कम

ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जोनाथन बैम्बर ने कहा- सुरक्षित सीमा' का मतलब है ऐसी स्थिति जिसमें लोग किसी तरह से हालात से निपट सकें, लेकिन अगर समुद्र का जलस्तर सालाना 1 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा की रफ्तार से बढ़ेगा, तो यह बेहद मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में बड़े पैमाने पर पलायन होगा – जैसा आधुनिक सभ्यता में कभी नहीं देखा गया।

गरीब देशों जैसे बांग्लादेश की स्थिति ज्यादा खराब होगी, जबकि नीदरलैंड जैसे विकसित देशों को कुछ हद तक राहत मिल सकती है क्योंकि वहां पहले से तटीय सुरक्षा मजबूत है।

भविष्य की चेतावनी

डरहम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्रिस स्टोक्स ने कहा कि वर्तमान तापमान वृद्धि (1.2एष्ट) पर भी समुद्र स्तर तेजी से बढ़ रहा है।

अगर यह गति जारी रही, तो सदी के अंत तक यह संभाल पाना नामुमकिन हो जाएगा – और यह आज के युवाओं के जीवनकाल में ही होगा।

इतिहास से सबक

लगभग 3 मिलियन साल पहले जब वातावरण में CO_2 का स्तर आज जितना था, तो समुद्र का जलस्तर 10-20 मीटर ऊँचा था। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ग्रह्र को हटाकर हम तापमान नीचे भी ले आएं, तब भी बर्फ की चादरों को वापस बनने में सैकड़ों-हजारों साल लगेंगे। यानी जो ज़मीन समुद्र में डूब गई, वो बहुत लंबे समय तक डूबी रहेगी।

एक उदाहरण

1970 में बेलीज ने तूफान के बाद अपनी राजधानी को तट से हटाकर अंदर शिफ्ट कर दिया था, लेकिन उसका सबसे बड़ा शहर अब भी तट पर है, जो सिर्फ 1 मीटर समुद्र स्तर बढ़ने से डूब जाएगा।

बेलीज के जलवायु वार्ताकार कार्लोस फुलर ने कहा-

इस तरह के शोध दिखाते हैं कि पेरिस समझौते में तय 1.5एष्ट सीमा के भीतर रहना कितना जरूरी है, ताकि हम तापमान को कम कर सकें और अपने तटीय शहरों की रक्षा कर सकें।

कुहू इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित हुआ निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर

246 अभिभावकों एवं विद्यार्थियों ने लिया लाभ

विशेष संवाददाता

गंगापुर सिटी।सोमवार को कुहू इंटरनेशनल स्कूल गंगापुर सिटी में विप्र फाउंडेशन एवं सीपी हॉस्पिटल मल्टीस्पेशियलिटी हेल्थ केयर सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में एक निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में कुल 246 अभिभावकों एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया और विभिन्न स्वास्थ्य जांचों का लाभ उठाया।

इस शिविर में विशेष रूप से हड्डी रोग, नाक, कान एवं गला रोग, नेत्र रोग, जनरल मेडिसिन तथा दंत रोग से संबंधित परामर्श और जांच की सुविधाएं प्रदान की गईं। विद्यार्थियों द्वारा मुख्यत: आँखों एवं दांतों की जांच कराई गई जबकि अभिभावकों ने बीपी, शुगर एवं अन्य सामान्य बीमारियों की जांच करवाई।

शिविर के समापन पर विप्र फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. हेमंत शर्मा ने सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं सीपी हॉस्पिटल के प्रबंधन टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विप्र फाउंडेशन भविष्य में भी इसी प्रकार के निशुल्क जांच शिविर आयोजित करता रहेगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। शिविर में शिविर संयोजक डॉ. क्षितिज गुप्ता (निदेशक, सीपी हॉस्पिटल), सहयोगी संस्था PGI सोनीपत (BPSGMC हरियाणा) तथा सम्पर्क सूत्र मनोज शर्मा की भी सराहनीय भूमिका रही।

रणथम्भौर में टेरेटरी की जंग, बाघिन एरोहेड और नूरी में संघर्ष

सवाईमाधोपुर। रणथम्भौर में युवा होते बाघ-बाघिन अब अपने इलाके को लेकर अन्य बाघ बाघिनों को चुनौती पेश करने लगे हैं। ताजा मामला रणथम्भौर के जोन दो में सामने आया है।

जानकारी के अनुसार गत दिनों रणथम्भौर के जोन दो में बाघिन एरोहैड यानि टी-84 और बाघिन नूरी यानि टी-105 में इलाके को

लेकर हल्की झड़प और संघर्ष देखने को मिला। हालांकि कुछ देर के बाद दोनों बाघिने शांत हो गई और दोनों दूसरे इलाके में चली गईं।

वन अधिकारियों की माने तो युवा बाघ-बाघिन इलाके को लेकर आम तौर पर एक दूसरे को चुनौती पेश करते हैं और कमजोर बाघ-बाघिन को इलाका छोड़ना पड़ता है।

वर्तमान में बाघिन एरोहैड की बेटी की उम्र डेढ़ साल से अधिक हो गई है और वह अब अपने लिए टेरेटरी की तलाश कर रही है। हालांकि अब तक वन विभाग की ओर से एरोहैड के शावकों को नम्बर जारी नहीं किए गए हैं।

व्यापारियों ने तुर्किये के सेब का किया बहिष्कार

जयपुर। राजस्थान के अलवर जिले में व्यापारियों ने तुर्किये से आयात किये जाने वाले सेबों का बहिष्कार शुरू कर दिया है। व्यापारियों ने कहा कि अब अलवर व आसपास की मंडियों में तुर्किये के सेब नहीं बिकेंगे।

अलवर के व्यापारियों ने भारत के साथ हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान तुर्किये द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देने के विरोध में यह फैसला किया है। इससे पहले अजमेर में संगमरमर पत्थर व्यापारियों ने भी इसी मुद्दे को लेकर तुर्किये का बहिष्कार शुरू कर दिया था।

यह निर्णय जनता की भावना को दर्शाता है

'अलवर फल मंडी यूनियन' ने तुर्किये से आयातित सेबों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने की घोषणा की है। व्यापारियों ने कहा कि यह निर्णय जनता की भावना को दर्शाता है और इसका उद्देश्य तुर्किये के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाना है।

हर दिन 15 टन से अधिक तुर्किये के सेब आते थे

'फल मंडी यूनियन' के महासचिव सौरभ कालरा ने बताया, %मार्च से जून के बीच हर दिन 15 टन से अधिक तुर्किये के सेब राजस्थान में आते हैं।% उन्होंने कहा, %लेकिन तुर्किये के भारत विरोधी रुख के कारण हमने अब ये सेब नहीं बेचने का फैसला किया है। यह सिर्फ कारोबारी फैसला नहीं है बल्कि एक संदेश है।

लगाए जाएंगे पोस्टर

शुक्रवार से दुकानों में 'तुर्किये सेब का बहिष्कार' का आह्वान करने वाले पोस्टर लगाए जाएंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा कि बाजार में कोई भी तुर्किये सेब न बिके।

माना जाएगा देशद्रोह

कालरा ने कहा, अगर कोई व्यापारी तुर्किये का सेब बेचते पाया गया तो इसे 'देशद्रोह' माना जाएगा। संघ के सचिव पंकज सैनी ने कहा कि सेब की मांग को पूरा करने के लिए कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दक्षिण अफ्रीका जैसे वैकल्पिक स्रोत तैयार हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए उनके पास 'कोल्ड स्टोरेज' में पर्याप्त भंडार है।

पर्यटकों से तुर्किये न जाने की भी अपील

व्यापारियों ने जनता से तुर्किये घूमने फिरने न जाने की अपील की। सैनी ने कहा, %भारतीयों को दूसरे पर्यटक गंतव्य चुनने चाहिए। अगर तुर्किये पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, तो हम आर्थिक रूप से जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि यह कदम दिल्ली और मुंबई के फल मंडियों में भी इसी प्रकार के बहिष्कार की खबरों के बाद उठाया गया है।

कुहू इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित हुआ नि:शुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लगाए बेजुबान पक्षियों के लिए परिंडे

विशेष संवाददाता

गंगापुर सिटी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई गंगापुर सिटी द्वारा भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए शहर के सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे मन्दिर परिसर, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, धर्मशाला, चिकित्सालय, कालेज प्रांगण, थाना, कोर्ट कचहरी आदि सार्वजनिक स्थानों पर परिंडे बांधने का अभियान चलाया जा रहा है इस कार्यक्रम की शुरुआत कर्मचारी कॉलोनी हनुमान जी के मन्दिर प्रांगण में भाजपा नेता सुशील दीक्षित द्वारा परिंडे बांध कर की । आज शहर में हनुमान जी का मन्दिर, नरूका पेट्रोल पंप पर

दीपक जी नरुका, मोक्ष धाम ईदगाह मोड पर शिवरतन गुप्ता सभापति नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा परिंडे बांधे गए।

इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मनोज कुमार सैनी जिला संयोजक, सीताराम गुर्जर पूर्व प्रान्त सह संयोजक (एस एफ एस) ओमप्रकाश गुर्जर नगर अध्यक्ष गंगापुर सिटी, मनोज कुमार गुप्ता नगर अध्यक्ष बामनवास, सुरेश चन्द्र गुप्ता, विकास कुमार सैनी, अजीत सिंह गुर्जर, संजय गुर्जर, राजेश शर्मा, जीतेन्द्र गुर्जर, राहुल कुमार जागा बदन सिंह गुर्जर आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। मो. नं. 9928078717